नॉन एसबीआई-एटीएम चार्ज हुआ महंगा

सैलरी अकाउंट पर अब केवल 10 फ्री ट्रांजेक्शन ही संभव

नई दिल्ली, 13 जनवरी. सैलरी अकाउंट धारकों के लिए अब महीने में केवल 10 फ्री ट्रांजेक्शन मिलेंगे, जबकि पहले यह अनलिमिटेड थे. वहीं रेगुलर सेविंग्स अकाउंट में 5 फ्री ट्रांजेक्शन का नियम पहले जैसा ही है. बैंक ने इंटरचेंज फीस बढ़ने को इसका कारण बताया. एसबीआई एटीएम और योनो कैश के माध्यम से ट्रांजेक्शन पूरी तरह फ्री रहेंगे.

ग्राहकों को सुझाव दिया गया है कि वे अपने फ्री लिमिट ट्रैक करें और डिजिटल बैंकिंग के माध्यम से शुल्क से बचें. यह बदलाव लाखों ग्राहकों की रोजमर्रा की बैंकिंग पर असर डाल सकता है, खासकर छोटे शहरों में.

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने नॉन- एसबीआई एटीएम से कैश निकासी और अन्य ट्रांजेक्शन के शुल्क में बदलाव की घोषणा की है. 1 दिसंबर 2025 से लागू हुए नियमों के अनुसार, अब नॉन-एसबीआई एटीएम से कैश निकालने पर फ्री लिमिट खत्म होने के बाद ?23 + जीएसटी देना होगा. नॉन-फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन जैसे बैलेंस चेक और मिनी स्टेटमेंट पर 11 + जीएसटी चार्ज लगेगा. सैलरी अकाउंट होल्डर्स के लिए बदलाव सबसे बड़ा है. पहले वे अनलिमिटेड फ्री ट्रांजेक्शन कर सकते थे, अब केवल महीने में 10 फ्री ट्रांजेक्शन मिलेंगे. लिमिट खत्म होने के बाद नए शुल्क लागू होंगे. वहीं रेगुलर सेविंग्स अकाउंट धारकों के लिए फ्री ट्रांजेक्शन की संख्या पहले जैसी ही है, 5 फ्री ट्रांजेक्शन हर माह.

बैंक ने कहा कि यह बदलाव इंटरचेंज फीस बढ़ने के कारण किया गया है. इंटरचेंज फीस वह शुल्क है जो बैंक दूसरे बैंक के एटीएम का उपयोग करने पर चुकाता है. बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट और किसान क्रेडिट कार्ड अकाउंट धारकों पर कोई नया शुल्क नहीं लगाया गया है. एसबीआई के एटीएम और योनो कैश से ट्रांजेक्शन पूरी तरह फ्री रहेंगे. ग्राहकों को सलाह दी गई है कि वे अधिकतर एसबीआई एटीएम का उपयोग करें, डिजिटल बैंकिंग के माध्यम से बैलेंस चेक और फंड ट्रांसफर करें और महीने में फ्री लिमिट ट्रैक करें.

> यह बदलाव विशेष रूप से छोटे शहरों में रहने वाले ग्राहकों को प्रभावित कर सकता है, जहां एसबीआई एटीएम कम हैं. बैंक ने अपने ग्राहकों से अनुरोध किया है कि वे अपने अकाउंट की डिटेल्स नियमित रूप से देखें और आवश्यकता पड़ने पर ब्रांच से संपर्क करें. विशेषज्ञों का कहना है कि डिजिटल और मोबाइल बैंकिंग विकल्पों का अधिक इस्तेमाल करने से ग्राहक अतिरिक्त चार्ज से बच सकते हैं.

भारत का टैक्स कलेक्शन मजबूत, 8.82 प्रतिशत बढ़ोतरी

नई दिल्ली,13 जनवरी. चालू वित्त वर्ष में 11 जनवरी तक भारत का शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह 8.82 प्रतिशत से बढ़कर 18.38 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गया. आयकर विभाग द्वारा जारी आंकड़ों में यह जानकारी दी गयी.

आयकर विभाग के अनुसार कुल संग्रह में 8.63 लाख करोड़ रुपये से अधिक का शुद्ध कॉर्पोरेट कर संग्रह शामिल है, जबकि व्यक्तियों, हिंदू अविभाजित परिवारों (एचयूएफ) और अन्य संस्थाओं सहित गैर-कॉर्पोरेट संस्थाओं से एकत्र किया गया कर 9.30 लाख करोड़ रुपये रहा. एक अप्रैल से 11 जनवरी के बीच प्रतिभूति लेनदेन कर (एसटीटी) से 44,867 करोड़ रुपये का संग्रह हुआ, जो पूंजी बाजारों में स्थिर गतिविधि को दर्शाता है.

सोना-चांदी दूसरे दिन भी ऑलटाइम हाई

1.40 लाख रुपए पार हुआ सोना | 2.63 लाख रुपए पहुंची चांदी

नई दिल्ली,13 जनवरी. देश के सर्राफा बाजार में सोना और चांदी ने नया इतिहास रच दिया है. 13 जनवरी को दोनों की कीमतें लगातार दूसरे दिन ऑल टाइम हाई पर पहुंच गई. इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार चांदी दो दिन में करीब कै. 20,000 **महंगी होकर कै.2.63 लाख प्रति किलो तक पहुंच गई है, जबकि 24 कैरेट सोना कै.1.4 लाख प्रति** 10 **ग्राम के पार निकल गया है.**

डॉलर की कमजोरी, वैश्विक तनाव और मजबूत औद्योगिक मांग इस तेजी को और हवा दे रही है. घरेलू सर्राफा बाजार में सोना और चांदी की कीमतों ने नया रिकॉर्ड बना दिया है. लगातार दूसरे

दिन दोनों कीमती धातुएं ऑल टाइम हाई पर पहुंच गईं. इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार, एक किलो चांदी की कीमत 6,566 रुपये बढ़कर 2,62,742 रुपये हो गई, जबकि 24 कैरेट सोना 33 रुपये की बढ़त के साथ 1,40,482 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया. बीते दो दिनों में चांदी की कीमतों में लगभग 20 हजार रुपये की तेज उछाल देखने को मिली है. वहीं सोने ने भी निवेशकों को चौंकाते हुए नई ऊंचाइयों को छू लिया है. बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता और डॉलर की कमजोरी से सोने की मांग तेज हुई है.

> वहीं अमेरिका में संभावित टैरिफ बढ़ोतरी के डर से कंपनियां भारी मात्रा में चांदी का स्टॉक जमा कर रही हैं, जिससे वैश्विक आपूर्ति पर दबाव बढ़ा है. केडिया एडवाइजरी के डायरेक्टर अजय केडिया के अनुसार, चांदी इस साल 2.75 लाख रुपये प्रति किलो तक जा सकती है, जबकि सोना भी साल के अंत तक 1.50 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम का स्तर पार कर सकता है. निवेशकों के लिए यह दौर ऐतिहासिक तेजी का संकेत दे रहा है.

शेयर बाजारों में गिरावट, सेंसेक्स 250 अंक टूटा

मुंबई, 13 जनवरी. विदेशों से मिले मिश्रित संकेतों के बीच घरेलू शेयर बाजारों में मंगलवार को गिरावट रही और बीएसई का सेंसेक्स 250.48 **अंक** (0.30 **फीसदी) टूटकर 83,627.69 अंक पर बंद हुआ. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) का निफ्टी-5 सूचकांक भी 57.95 अंक यानी** 0.22 **प्रतिशत गिरकर 25,732.3 अंक पर रहा.**

टिकाऊ उपभोक्ता उत्पाद, रियलिटी, फार्मा, तेल एवं गैस, ऑटो और एफएमसीजी सेक्टरों के सूचकांक लाल निशान में रहे. आईटी, बैंकिंग, मीडिया और रसायन समूहों के सूचकांक हरे निशान में बंद हुए. सेंसेक्स की कंपनियों में ट्रेंट और एलएंडटी में तीन प्रतिशत से अधिक की गिरावट रही. रिलायंस इंडस्ट्रीज

और इंडिगो के शेयर भी लगभग दो फीसदी टूटे. मारुति सुजुकी, आईटीसी, अडानी पोर्ट्स और बीईएल के शेयर एक प्रतिशत से ज्यादा गिरे. एक्सिस बैंक, भारती एयरटेल, हिंदुस्तान यूनीलिवर, महिंद्रा एंड महिंद्रा, अल्ट्राटेक सीमेंट, सनफार्मा, टाटा स्टील और बजाज फाइनेंस के शेयर भी लाल निशान में बंद हुए. इटरनल का शेयर सवा तीन फीसदी की बढ़त में बंद हुआ.

टेक महिंद्रा, आईसीआईसीआई बैंक और भारतीय स्टेट बैंक के शेयर एक प्रतिशत से अधिक चढ़े. टीसीएस में भी लगभग एक प्रतिशत की तेजी रही. एनएसई में मझौली कंपनियों के सूचकांकों में गिरावट रही. निफ्टी मिडकैप-50 सूचकांक 0.30 प्रतिशत गिर गया. छोटी कंपनियों के स्मॉलकैप-100 सूचकांक में 0.60 प्रतिशत की तेजी रही.

चावल, गेहूं, चीनी, खाद्य तेलों के दाम बढ़े, दालों में घट-बढ़

नई दिल्ली, 13 जनवरी. घरेलू थोक जिंस बाजारों में मंगलवार को चावल के औसत भाव बढ़े. चावल के साथ जहां गेहूं, चीनी और खाद्य तेलों में भी तेजी रही. वहीं, दालों में उतार-चढ़ाव देखा गया. औसत दर्जे के चावल की औसत कीमत 21 रुपये बढ़कर 3,863 रुपये प्रति क्विंटल पर पहुंच गयी. गेहूं सात रुपये महंगा हुआ और 2,864 रुपये प्रति क्विंटल पर रहा. आटे की कीमत भी पांच रुपये बढ़ गयी. दाल-दलहनों में मिलाजुला रुख रहा. तुअर दाल औसतन नौ रुपये प्रति क्विंटल सस्ती हुई. वहीं, मसूर दाल के दाम 42 रुपये और मूंग दाल के 35 रुपये बढ़ गये. चना दाल सात रुपये और उड़द दाल तीन रुपये प्रति क्विंटल महंगी हुई.

भारत-ईरान व्यापार 168 करोड़ डॉलर

नई दिल्ली, 13 जनवरी. भारत और ईरान के बीच द्विपक्षीय व्यापार महज 168.30 **करोड़ डॉलर पर है और इसका संतुलन भारत के पक्ष में है. वित्त वर्ष** 2024-25 **में भारत ने ईरान को 124.12 करोड़ डॉलर का निर्यात किया और आयात 44.18 करोड़ डॉलर रहा. पिछले चार वर्षों में तीन बार व्यापार में गिरावट दर्ज हुई है.**

भारत ईरान से मुख्य रूप से फलों, सूखे मेवे और खजूर का आयात करता है. ईरान के साथ भारत का द्विपक्षीय व्यापार महज 168.30 करोड़ डॉलर है, और इसमें व्यापार संतुलन भारत के पक्ष में है. वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के आंकड़े बताते हैं कि भारत ने वित्त वर्ष 2024-25 में ईरान को 124.12 करोड़ डॉलर का निर्यात किया. यह भारत के

कुल निर्यात का 0.14 प्रतिशत है. दूसरी तरफ ईरान से भारत का आयात 44.18 करोड़ डॉलर रहा जो देश के कुल आयात का महज 0.06 प्रतिशत है. दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार के स्तर में पिछले कुछ समय से लगातार गिरावट आ रही है. पिछले चार वित्त वर्षों में से तीन में व्यापार घटा है. इसमें 2023-24 में 20.75 प्रतिशत और 2024-25 में 8.90 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गयी. इससे पहले, 2020-21 में भी यह 9.10 फीसदी घटा था जबकि 2022-23 में 21.77 प्रतिशत की बढ़त दर्ज की गयी थी. पिछले साल जहां ईरान से आयात में 29.32 प्रतिशत की भारी गिरावट दर्ज की गयी, वहीं निर्यात 0.14 प्रतिशत बढ़ा. भारत ईरान से मुख्य रूप से फलों, सूखे मेवे, खजूर आदि का आयात करता है.

रुपये में मामूली तेजी

मुंबई, 13 जनवरी अंतर बैंकिंग मुद्रा बाजार में रुपया सोमवार को 0.50 पैसे की मामूली तेजी

के साथ 90.1750 रुपये प्रति डॉलर पर बंद हुआ. इससे पहले भारतीय मुद्रा लगातार दो दिन कमजोर बंद हुई थी. पिछले कारोबारी दिवस पर यह 27.75 पैसे गिरकर 90.18 रुपये प्रति डॉलर पर रही थी. रुपया आज पांच पैसे की गिरावट के साथ 90.23 रुपये प्रति डॉलर पर खुला. यह नीचे 90.14 रुपये और ऊपर 90.25 रुपये प्रति डॉलर तक गया.विदेशी संस्थागत निवेशकों के भारतीय पूंजी बाजार से पैसा निकालने से रुपये पर दबाव रहा. वहीं, दुनिया की अन्य प्रमुख मुद्राओं के बास्केट में डॉलर के कमजोर पड़ने से भारतीय मुद्रा को समर्थन मिला.

रिजर्व बैंक ने खरीदी 50,000 करोड़ की सरकारी प्रतिभूतियां

मुंबई,13 जनवरी. रिजर्व बैंक ने सोमवार को खुले बाजार से 50,000 **करोड़ रुपये की सरकारी प्रतिभूतियां खरीदीं.**

केंद्रीय बैंक ने वाणिज्यिक बैंकों के पास नकदी की उपलब्धता बढ़ाने के उपायों के तहत यह खरीद की है. यह चार समान किस्तों में दो लाख करोड़ रुपये की सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद के तहत तीसरी किस्त है. रिजर्व बैंक की प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया है कि उसने सात तरह की प्रतिभूतियों की खरीद की है जिनकी मियाद साल 2029 से 2053 तक अलग-अलग समय में पूरी हो रही है. इसमें तीन साल, पांच साल, छह साल, आठ साल, नौ साल, 11 साल और 27 साल की प्रतिभूतियां शामिल हैं. इन प्रतिभूतियों पर 6.64 प्रतिशत से 8.32 प्रतिशत ब्याज दर हैं. पहली किस्त में 50 हजार करोड़ रुपये की सरकारी प्रतिभूतियां 29 जनवरी को खरीदी गयी थीं. दूसरी किस्त के तहत 05 जनवरी को खरीद की गयी थी.

यात्री वाहनों की बिक्री 27 प्रतिशत बढ़ी

नई दिल्ली, 13 जनवरी. देश में यात्री वाहनों की थोक बिक्री 26.8 प्रतिशत बढ़कर 3,99,216 इकाई पर पहुंच गयी. यात्री वाहनों में कारें, उपयोगी वाहन और वैन शामिल होते हैं.

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) में नयी पीढ़ी के सुधारों और रिजर्व बैंक द्वारा रेपो दरों में कटौती से ऋण पर ब्याज कम होने के कारण पूरी तिमाही में मांग मजबूत बनी रहने से तिमाही और सालाना बिक्री का भी नया रिकॉर्ड बना है. वाहन निर्माता कंपनियों के संगठन सियाम द्वारा मंगलवार को जारी आंकड़ों में बताया गया है कि दिसंबर 2025 में दुपहिया वाहनों की बिक्री 39.4 फीसदी बढ़कर 15,41,036 इकाई दर्ज की गयी. तिपहिया की बिक्री 61,924 इकाई पर रही जो एक साल पहले के मुकाबले 17.4 प्रतिशत अधिक है. अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में यात्री वाहनों की बिक्री 20.6 फीसदी बढ़कर 12,76,073 इकाई

रही जिसमें 8,52,498 उपयोगी वाहन शामिल हैं. कारों की बिक्री 20.5 प्रतिशत, उपयोगी वाहनों की 20.9 प्रतिशत और वैन 16.4 प्रतिशत बढ़ी है. वर्ष 2025 की अंतिम तिमाही में दुपहिया की बिक्री 16.9 प्रतिशत बढ़कर 56,96,238 इकाई पर पहुंच गयी.

एचसीएल टेक्नोलॉजीज का तिमाही मुनाफा 4.5 प्रतिशत बढ़ा

नई दिल्ली, 13 जनवरी. सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र की अग्रणी कंपनी एचसीएल टेक्नोलॉजीज का शुद्ध लाभ चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही (अक्टूबर-दिसंबर) में 4.5 प्रतिशत बढ़कर 4,795 करोड़ रुपये पर पहुंच गया.

कंपनी ने प्रति शेयर 12 रुपये के लाभांश की घोषणा की है जिसके लिए रिकॉर्ड की तारीख 16 जनवरी रखी गयी है और भुगतान 27 जनवरी को किया जायेगा. यह लगातार 92वीं तिमाही है जब कंपनी ने राजस्व की घोषणा की है.

एनपीएस में सुनिश्चित पेंशन को लेकर बनी समिति

नई दिल्ली, 13 जनवरी. राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत निवेशकों को सुनिश्चित पेंशन भुगतान उपलब्ध कराने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए पेंशन कोष विनियामक एवं फंड विकास प्राधिकरण ने एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है.

इस समिति की अध्यक्षता भारतीय दिवाला एवं ऋण शोधन अक्षमता बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष और रेगुलेटरी चैंबर्स के संस्थापक डॉ. एम. एस. साहू करेंगे. मंत्रालय की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार 15 सदस्यीय इस समिति में कानून, बीमा, वित्त, पूंजी बाजार और शिक्षा जैसे क्षेत्रों के विशेषज्ञ शामिल किए गए हैं. जरूरत पड़ने पर समिति को विशेषज्ञों को आमंत्रित करने का भी अधिकार दिया गया है ताकि सुझाव व्यापक और व्यावहारिक बन सकें. इस समिति को व्यवस्थित पेंशन भुगतान पर एक स्थायी सलाहकार निकाय का दर्जा दिया गया है. इसका उद्देश्य एनपीएस के अंतर्गत सुनिश्चित भुगतान की व्यवस्था को नियमों और दिशानिर्देशों के जरिए मजबूत करना है.

समाचार विशेष

पंजाब चुनाव में चन्नी होंगे कांग्रेस के सीएम फेस!

हाईकमान ने वड़िंग-रंधावा को कुर्सी की रेस से किया बाहर

चंडीगढ़. पंजाब में 2027 **के विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की अगुआई की तस्वीर धीरे-धीरे स्पष्ट होती जा रही है. एक मीडिया रिपोर्ट में कांग्रेस के अंदर से मिल रही जानकारी के आधार पर बताया गया कि पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी को पार्टी आगामी चुनावी अभियान में नेतृत्व सौंपने जा रही है.**

यह संकेत कांग्रेस की मनरेगा बचाओ रैलियों से मिल रहे हैं, जिनमें प्रदेश अध्यक्ष सांसद अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग और सांसद सुखजिंदर सिंह रंधावा ने मुख्यमंत्री कुर्सी का दावा छोड़ दिया है. वहीं, नवजोत सिंह सिद्धू पहले ही सक्रिय राजनीति से बाहर हो चुके हैं. हालांकि, कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रताप बाजवा अभी भी मुख्यमंत्री के पद को लेकर

जोर-शोर से अपना दावा पेश कर रहे हैं. वह रैलियों में सरकार आने पर कार्रवाई का ऐलान कर रहे हैं, जिससे यह साफ होता है कि वह खुद को छ्रू चेहरे की दौड़ में बनाए हुए हैं. इसके विपरीत, चरणजीत चन्नी पार्टी के भीतर साइलेंट पॉलिटिक्स कर रहे हैं. चन्नी को सोशल मीडिया और पार्टी के भीतर से अच्छा समर्थन मिल रहा है, लेकिन वह किसी भी तरह का दावा या बयान देने से बच रहे हैं.

> **प्रताप बाजवा के सीएम चेहरे वाले तेवर**
>
> प्रताप बाजवा अभी भी अपनी दावेदारी में अड़े हुए हैं और चुनावी मंचों से लगातार बयान दे रहे हैं. हालांकि, कांग्रेस पार्टी के भीतर कोई स्पष्ट संदेश अभी तक नहीं आया है कि किसे पार्टी का मुख्यमंत्री चेहरा माना जाएगा. बाजवा की दावेदारी के पीछे उनकी राजनीति और कार्यशैली के कारण माहौल गर्म है, लेकिन यह भी कहा जा रहा है कि पार्टी हाईकमान इस मुद्दे पर जल्द ही कोई फैसला ले सकता है.

चन्नी की दावेदारी क्यों मजबूत?- तीन महीने में बने लोकप्रिय-2021 में जब कांग्रेस ने कैप्टन अमरिंदर सिंह को मुख्यमंत्री पद से हटाया, तब चरणजीत चन्नी को मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया था. चन्नी को सिर्फ 3 महीने का समय मिला.

केसी त्यागी क्यों निशाने पर?

पटना. जनता दल यू के नेताओं ने अचानक केसी त्यागी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता से लेकर अन्य नेता व प्रवक्ता उनके खिलाफ बयान दे रहे हैं. कह रहे हैं कि केसी त्यागी ने पार्टी लाइन से अलग हट कर बयान दिया.

वे इस बात से नाराज हैं कि केसी त्यागी ने कैसे नीतीश कुमार को भारत रत्न देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है. उनको लग रहा है कि यह भाजपा की राजनीति का हिस्सा है कि नीतीश को भारत रत्न देकर उनको रिटायर कराया जाए और भाजपा अपना मूख्यमंत्री बनाए. लेकिन इसका कोई आधार नहीं है. पंडित जवाहर लाल नेहरू को भी 1955 में भारत रत्न मिला था और वे उसके बाद नौ साल तक प्रधानमंत्री बने रहे थे. सो, नीतीश भारत रत्न प्राप्त करके भी मुख्यमंत्री बने रह सकते हैं.

केसी त्यागी के खिलाफ इस बात को लेकर भी नाराजगी जताई जा रही है कि उन्होंने बांग्लादेश के क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान की तरफदारी की और उनको आईपीएल टीम से निकाले जाने का विरोध किया. लेकिन यह भी तो नीतीश कुमार की राजनीति के अनुकूल ही लाइन थी.

महाराष्ट्र के अंबरनाथ में हुआ नया खेला

ठाणे. महाराष्ट्र में ठाणे जिले की अंबरनाथ में सियासी पिक्चर अभी बाकी है. अंबरनाथ नगर परिषद की राजनीति में एक बार फिर नया मोड़ आ गया है. अंबरनाथ में भाजपा को अजित पवार की एनसीपी ने बड़ा झटका दिया है. पहले भाजपा ने एकनाथ शिंदे की शिवसेना को दूर रखने के लिए कांग्रेस से गठबंधन किया था.

अब एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने भाजपा को अंबरनाथ की सत्ता से दूर रखने के लिए अपनी नई चाल चल दी है. जी हां, अंबरनाथ में एकनाथ शिंदे की शिवसेना, अजित पवार गुट की एनसीपी और एक निर्दलीय पार्षद ने हाथ मिला लिया है. इतना ही नहीं, अंबरनाथ की सत्ता पर अपना दावा भी ठोक दिया है.

दरअसल, एकनाथ शिंदे की शिवसेना, अजित पवार की एनसीपी और एक निर्दलीय पार्षदों का अंबरनाथ में गठबंधन हुआ है. इन तीनों ने मिलकर अंबरनाथ नगर परिषद की सत्ता

पर अपना दावा ठोक दिया है. इससे बीजेपी को सत्ता से दूर रखने की कोशिश की जा रही है.

यहां बताना जरूरी है कि इससे पहले अजित पवार की एनसीपी अंबरनाथ में भाजपा के साथ थी. मगर अब एनसीपी ने एकनाथ शिंदे की शिवसेना को समर्थन दे दिया है. बहरहाल, अंबरनाथ में एकनाथ शिंदे की शिवसेना, अजित पवार की एनसीपी और एक निर्दलीय पार्षद वाले इस नए गठबंधन की जानकारी जिला प्रशासन को लिखित रूप में दे दी गई है. यह घटनाक्रम ऐसे समय पर सामने आया है, जब हाल ही में कांग्रेस के निलंबित 12 पार्षद बीजेपी में शामिल हुए थे.

देवेंद्र फडणवीस ने क्या लॉजिक दिया?

अंबरनाथ में कांग्रेस और भाजपा गठबंधन पर देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि यहां हमारा टेक्निकली कांग्रेस से गठबंधन हुआ ही नहीं. यह गलत नैरेटिव है. लोकल लेवल पर भाजपा और शिवसेना के नेताओं में दुश्मनी के कारण ही हमारा एकनाथ शिंदे की शिवसेना से गठबंधन नहीं हो पाया. इसके बाद लोकल लेवल पर भाजपा नेताओं ने कांग्रेस को तोड़ने की कोशिश की. इस कोशिश को कांग्रेस ने गठबंधन कहकर प्रचार किया. इसके बाद कांग्रेस ने अपने पार्षदों को पार्टी से निकाल दिया. वे सभी कांग्रेसी पार्षद भाजपा में मिल गए. इस तरह हमारा अंबरनाथ में कांग्रेस से अलायंस नहीं हुआ. यह सब लोकल लेवल पर हुआ. बहुत सी बातें हम तक नहीं पहुंचती.

विशेष | नीतीश कुमार अब हरिवंश नारायण सिंह को नहीं भेजेंगे राज्यसभा!

देश को मिलेंगे नए उपसभापति?

नई दिल्ली. राज्यसभा में बदलाव को लेकर बड़ी खबर सामने आई है. इस साल राज्यसभा को नया उपसभापति मिल सकता है. इसके पीछे की वजह मौजूदा उपसभापति हरिवंश नारायण का कार्यकाल खत्म होना है.

दरअसल, अप्रैल में हरिवंश का कार्यकाल समाप्त हो रहा. हरिवंश राजनीति में जाना-पहचाना चेहरा हैं. वो नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड से दो बार राज्यसभा के सांसद रहे हैं. सूत्रों की मानें तो इस बार पार्टी हरिवंश की जगह नए चेहरे को राज्यसभा भेज सकती है. ऐसे में राज्यसभा के उपसभापति के चुनाव होना तय माना जा रहा. बता दें, हरिवंश नारायण 2018 से राज्यसभा के उपसभापति हैं. मगर, अब तीसरी बार उनका राज्यसभा जाना मुश्किल लग रहा है, क्योंकि जदयू इस बार जातिगत और अन्य समीकरणों को देख किसी और नेता को राज्यसभा भेजना चाहती है. जदयू का यह कदम उनकी रणनीति का हिस्सा है.

बिहार में खाली होंगी 5 सीटें- अप्रैल में बिहार से राज्यसभा की 5 सीटें भी खाली होंगी. वैसे, ऐसा कहा जा रहा कि इन सीटों में से 4 सीटों पर एनडीए का जीतना तय है. इन्हीं जीती हुई सीटों में से 1 या 2 सीट जदयू के खाते में जाएंगी. ऐसे में समीकरण और रणनीति की बात की जाए तो जदयू के वरिष्ठ नेता सह केंद्रीय मंत्री और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर के बेटे रामनाथ ठाकुर को फिर सीट मिलना तय माना जा रहा है. साथ ही वे मोदी सरकार में मंत्री भी बने रहेंगे. जदयू अपने दूसरे सांसद हरिवंश नारायण सिंह को तीसरी बार राज्यसभा नहीं भेजने के पक्ष में दिख रहा है, क्योंकि उन्हें राज्यसभा के दो कार्यकाल मिल चुका है.

जदयू क्या कह रही?- जब विवाद सामने आया था तो हरिवंश नारायण सिंह ने तर्क दिया था कि वे एक संवैधानिक पद पर हैं, इसलिए इस्तीफा देना ठीक नहीं है. इसके लिए जदयू नेताओं ने उन्हें खूब घेरा भी था. फिलहाल उपसभापति पद को लेकर जदयू नेताओं का साफ कहना है कि यह काम बीजेपी का है, वही तय करेगी कि कौन होगा उपसभापति.

> **कैसे रहें नीतीश और हरिवंश के रिश्ते?**
>
> मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और हरिवंश नारायण सिंह के रिश्ते को लेकर कई बातें सामने आई हैं. पहले हरिवंश नारायण सिंह को नीतीश कुमार का काफी करीबी माना जाता है था. 2018 में बीजेपी ने हरिवंश को उपसभापति बनाने का प्रपोजल दिया था, तब नीतीश ने उन्हें सपोर्ट किया था. बाद में दोनों के रिश्ते में खटास आई, जब 2022 में नीतीश ने एनडीए का साथ छोड़ महागठबंधन का दामन थामा और नई सरकार बनाई. तब हरिवंश नारायण ने अपने पद से इस्तीफा देने से मना कर दिया था.